राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

वॉल्यूम 31, सं 4, अप्रैल, 2023

इंफोमेटिक्स

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ने नई दिल्ली में एक पोस्ट-बजट सेमिनार में शिकायत अपील समिति पोर्टल का अनावरण करते हुए

माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री ने शिकायत अपील समिति पोर्टल का अनावरण किया

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में बजट के बाद के सत्र में शिकायत अपील समिति (जीएसी) पोर्टल लॉन्च किया। श्री अलकेश कुमार शर्मा, सचिव, एमईआईटीवाई और अध्यक्ष, जीएसी, श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव, एमईआईटीवाई तथा एमईआईटीवाई के वरिष्ठ अधिकारी, एनआईसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित थे।

माननीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और आशा व्यक्त की कि जीएसी प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा और उनके मुद्दों को हल करने में एक सेतु के रूप में कार्य करेगा।

आईटी नियमों में सोशल मीडिया और अन्य मध्यस्थों को नियम 3(1)(ख) में निर्दिष्ट किसी भी जानकारी को अपने उपयोगकर्ताओं को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, स्टोर, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करके सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

आईटी नियम और जीएसी का उद्देश्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। जीएसी आईटी नियमों के उल्लंघन और बिचौलियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर सोशल मीडिया मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों के फैसलों से असंतुष्ट डिजिटल नागरिकों की अपील से निपटता है। अपील दाखिल करने से लेकर निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में है, और जीएसी 30 दिनों के भीतर अपीलों को हल करने का प्रयास करती है। इसमें नागरिकों, मध्यस्थों और तीन GAC समितियों के नाम से तीन इंटरफेस हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए, पोर्टल एसएसओ समर्थित है। नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप को पोर्टल में जोड़ा जाएगा ताकि अपील को आसानी से दाखिल किया जा सके और एक हिंदी संस्करण भी जोड़ा जाएगा।

पोर्टल एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा एमईआईटीवाई और एनआईसी मुख्यालय के परामर्श से डिजाइन और विकसित किया गया है, और इसे https://gac.gov.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

- अजय सिंह चहल, हिमाचल प्रदेश

माननीय कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री, असम ने डिजिटल आईटीआई की शुरुआत की

माननीय कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री, असम सरकार, श्री जयंत मल्ला बरुआ ने गुवाहाटी में डिजिटल आईटीआई अनुप्रयोग के संबद्धता और भौतिक सत्यापन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह राज्य में आईटीआई की सभी प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण में मदद करेगा और ऑनलाइन संपर्क रहित संबद्धता को सक्षम करेगा। श्री बी. कल्याण चक्रवर्ती, प्रधान सचिव, एसईईडी; निदेशक, श्री हनीफ नूरानी, डीईसीटी; और श्रीमती कबिता रॉय दास, एनआईसी डीडीजी और एसआईओ असम, इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों में से थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल आईटीआई का शुभारंभ आईटीआई के ऑनलाइन संपर्क रहित संबद्धता को सक्षम करके असम में रोजगार के लिए और अधिक अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयास का पूरक होगा। उन्होंने सफल प्रक्षेपण के पीछे राज्य केंद्र के प्रयासों की भी सराहना की। यह अनुप्रयोग एसआईओ एनआईसी असम के तत्वावधान में श्री रुबैयत उल अली, एएसआईओ की अध्यक्षता में एनआईसी असम डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है।

- कविता बरकाकोटी, असम

माननीय कौशल विकास रोजगार और उद्यमिता मंत्री, श्री जयंत मल्ला बरुआ ने राज्य के लिए डिजिटल आईटीआई का शुभारंभ किया

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली ने भोजन, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया

दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 28 फरवरी, 2023 को माननीय एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली में भोजन, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए एक संशोधित एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया गया। नया पोर्टल दिल्ली में भोजन, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शी और समय पर निपटान प्रक्रिया के माध्यम से व्यापार करने में आसानी की सुविधा देकर दिल्ली में इन प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देना है। पोर्टल पूरी तरह से ऑनलाइन और फेसलेस है, जिससे दिल्ली पुलिस, एमसीडी/एनडीएमसी, फायर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी सभी प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा व्यापारियों के आवेदनों की व्यक्तिगत और एक साथ प्रसंस्करण की अनुमति मिलती है। इन एजेंसियों द्वारा जारी लाइसेंस/एनओसी पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

अपने संबोधन के दौरान सभा में, माननीय एलजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और समयसीमा निर्धारित की गई है। पोर्टल में एक स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम भी है जो आवेदकों को हर समय अपने आवेदनों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने सभी हितधारकों, विशेष रूप से एनआईसी-एमएचए और एनआईसी-एमसीडी के योगदान की प्रशंसा की।

- अमर सिंह, दिल्ली

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना भोजन, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

पंजाब सरकार के आवासों के आवंटन के लिए सीएस पंजाब ने ईआवास पोर्टल लॉन्च किया

चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के घरों के ऑनलाइन आवंटन के लिए एक पोर्टल श्री विजय कुमार जांजुआ, आईएएस, पंजाब के मुख्य सचिव द्वारा लॉन्च किया गया है।प्रणाली को एनआईसी पंजाब द्वारा विकसित और अनुकूलित किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने घोषणा की कि पहले चरण में चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल की विभिन्न श्रेणियों के 1257 सरकारी आवासों का ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। दूसरे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पंजाब पूल के सरकारी आवासों का आवंटन किया जाएगा। श्री कुमार राहुल, आईएएस, सचिव, सामान्य प्रशासन के अनुसार, आवास के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी https://eawas.punjab.gov.in पर उपलब्ध होगी। सरकारी अधिकारी पोर्टल की सूची ब्राउज़ करके अपनी पसंद के आधार पर उपलब्ध मकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

श्री विवेक वर्मा, एसआईओ और डीडीजी एनआईसी ने कहा कि यह प्रणाली कर्मचारियों के लिए आवास आवंटन की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगी। पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया गया है।

- परमिंदर कौर, पंजाब

सीएस पंजाब श्री विजय कुमार जंजुआ ने पंजाब सरकार के आवासों के ऑनलाइन आवंटन के लिए ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया

जम्मू और कश्मीर सरकारी विभागों की ऑनलाइन वैधानिक लेखापरीक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है

मुख्य सचिव, डॉ अरुण कुमार मेहता, आईएएस ने जम्मू और कश्मीर सरकार के लाइन विभागों के खातों के वैधानिक ऑडिट करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया। यह एप्लिकेशन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वित्तीय प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में एक और कदम है, जो एनआईसी जम्मू-कश्मीर की अन्य पहलों जैसे ऑनलाइन बजटिंग (बीईएएमएस), ई-ट्रेजरी, ऑनलाइन बिलिंग और क्लीयरेंस (जेकेपीएवाईएसवाईएस), सरकारी रसीद और लेखा प्रणाली (जेके जीआरएएस), और जनभागीदारी (जो स्वीकृत बजट का विवरण और सार्वजनिक कार्यों की स्थिति को सार्वजनिक डोमेन में रखता है) का बारीकी से पालन करता है। डॉ. मेहता ने इस सुविधा को बनाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग और एनआईसी जम्मू-कश्मीर की प्रशंसा की। यह कहा गया था कि यह एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में BEAMS/JK-PaySyS से डेटा के उपयोग और उपयोग के साथ सरकारी विभागों से वित्तीय जानकारी तक पहुँचने के लिए एक एकीकृत एकल मंच उपकरण है।

यह भी पता चला कि यह वेब-आधारित ऑडिट एक सुलभ और विश्लेषणात्मक तरीके से सभी चरणों में समझने योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ऑडिटर और ऑडिटी दोनों के साथ-साथ ऑडिट टीमों के प्रबंधन और ऑडिट शेड्यूल की परिभाषा के निर्बाध मानचित्रण में सहायता करता है। इसके अलावा, यह कॉन्फ़िगर करने योग्य रिपोर्ट टेम्प्लेट के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है जो पीडीएफ में उपलब्ध हैं और ईमेल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के साथ साझा की जा सकती हैं।

जैसा कि पहले बताया गया है, नियमित अद्यतन (अपडेट्स) पर ईमेल-आधारित अलर्ट भी लेखापरीक्षितों को उनकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजे जाते हैं। ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफॉर्म परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार ऑडिटिंग को सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर ऑडिट से संबंधित रिकॉर्ड के लिए एक रिपॉजिटरी के रूप में भी काम करता है और एक प्रभावी वित्तीय ऑडिट टूल है जो पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी सुधार करता है। लेखापरीक्षा से संबंधित सभी संचार इस प्रणाली के माध्यम से होने चाहिए, जो बहुत जरूरी जवाबदेही लाएगा।

मुख्य सचिव के अनुसार, इससे प्रक्रिया आसान और अधिक केंद्रित होगी। उन्होंने विभाग को लेखापरीक्षा के बाद और खातों के समवर्ती लेखापरीक्षा का एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। मुख्य सचिव ने

डॉ. अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर ने ऑनलाइन वैधानिक लेखापरीक्षा अनुप्रयोग का शुभारंभ किया।

कहा कि विश्वसनीयता और उत्पादकता के मामले में प्रणाली में सुधार किया जाएगा। उन्होंने अनुरोध किया कि विभागीय अधिकारी नए ऑडिट मैनुअल, जिसमें ई-ऑडिट शामिल है, को सभी कार्यालयों में वितरित करें ताकि वे नई प्रणालियों से अवगत हों। मुख्य सचिव ने उन्हें ई-ऑफिस से जोड़ने का भी निर्देश दिया ताकि अधिकारी संबंधित रिपोर्ट और लंबित ऑडिट पैरा देख सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षा अधिक संपूर्ण और व्यापक हो, भले ही लेखापरीक्षक भौतिक रूप से लेखापरीक्षितियों से न मिलें।

- मोहम्मद सलीम खान, जम्मू-कश्मीर

माननीय उपराज्यपाल लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किया

लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर ने कारगिल और लेह के दोनों पहाड़ी परिषदों के साथ इस पहल का स्वागत करते हुए केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) का शुभारंभ किया। 4 अंकों का यूएलपीआईएन भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में मदद करेगा और एक निर्णायक भूमि शीर्षक तक भी पहुंचेगा।

ULPIN को एक "गेम चेंजर" और भू-राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए 'SVAMITVA' में अगला कदम बताते हुए, श्री आर.के. माथुर ने लद्दाख में भू-राजस्व रिकॉर्ड के 100 प्रतिशत कवरेज और जल्द से जल्द अभ्यास पूरा करने के महत्व की जानकारी दी।

उन्होंने न केवल 'आबादी देह' (बसे हुए) क्षेत्रों बल्कि प्रशासन द्वारा दोनों पहाड़ी परिषदों की मदद से अपनी योजनाओं और निधियों के माध्यम से पूरे लद्दाख के संतृप्ति कवरेज की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी हुई आबादी-देह क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्रशासन, दोनों पहाड़ी परिषदों के साथ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ काम करेगा।

UPLIN योजना कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी, जिसमें भूमि संबंधी विवादों को अदालत में शीघ्रता से निपटाना और भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी अवांछित परिवर्तन पर रोक लगाने जैसे पुराने मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को बैंकों से ऋण लेने और किसानों की पंजीकृत भूमि पर कीटनाशकों और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने में भी फायदेमंद साबित होगी। भूमि के ऊर्ध्वाधर आयाम को रिकॉर्ड करने के लिए पहाड़ी भूमि के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड और भूमि क्षेत्रों को इकट्ठा करने के लिए यह योजना फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए एक वरदान होगी और लद्दाख के समग्र विकास में मदद करेगी।

माननीय उपराज्यपाल लद्दाख, श्री आर के माथुर ने लद्दाख के निवासियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का शुभारंभ किया

- सूचना विज्ञान न्यूज़डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

एनआईसी भुवनेश्वर द्वारा आयोजित ईए और इंडईए फ्रेमवर्क पर टेक-बूटकैंप में वक्ता और प्रतिभागी

एनआईसी भुवनेश्वर द्वारा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और इंडईए फ्रेमवर्क पर टेक-बूटकैंप का आयोजन

एनआईसी भुवनेश्वर द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए 9 फरवरी 2023 को एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (ईए) और इंडईए फ्रेमवर्क पर एक तकनीकी बूटकैंप-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री भास्कर ज्योति शर्मा, आईएएस, आयुक्त-सह-सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शासन के लिए एक उद्यम-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-गवर्नेंस समाधान अक्सर स्वतंत्र रूप से विकसित किए जाते हैं, और स्पष्ट दृष्टि, लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ विभागों में अंतर-संचालनीयता की आवश्यकता पर बल दिया। एक उद्यम ढांचा प्रणाली का एक व्यापक अध्ययन प्रदान करता है, जो ई-गवर्नेंस समाधानों के विकास को सक्षम बनाता है जो लचीला, लागत प्रभावी और बढ़ती सार्वजनिक अपेक्षाओं, सरकारी प्रक्रियाओं और गतिशील व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।

डॉ. पी. गायत्री, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक और CollabFiles और EA संसाधन प्रभाग, एनआईसी हैदराबाद के प्रमुख ने सूचित किया कि एनआईसी ने उद्यम कलाकृतियों के विकास और तैयारी में पर्याप्त नेतृत्व किया है।

कुछ पहलों में 107 विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, हिमाचल प्रदेश के लिए लोक सेवा आयोग-एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, डिजिटल एनआईसी आर्किटेक्चर, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, पुणे और लैंड हब एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (एलएचईएपी) ई-प्रगति का मॉड्यूल के साथ हाल ही में मेघालय सरकार आदि के लिए राज्य उद्यम वास्तुकला का विकास किया जा रहा है।

- हरा प्रसाद दास, ओडिशा

एनआईसी महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह पर बंदरगाह बैक ऑफिस मॉड्यूल लागू करता है

मुंबई बंदरगाह भारत में एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है, जो हर साल बड़ी संख्या में यात्रियों और चालक दल को संभालता है। अप्रवासन निकासी की सुविधा के लिए, अतीत में केंद्रीय अप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (CICS) का उपयोग किया गया है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी यात्री यातायात में तीव्र वृद्धि का कारण बना, जिसके लिए एक नए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के विकास की आवश्यकता थी जो यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके।

श्रीमती अलका मिश्रा डीडीजी और एचओजी (आईवीएफआरटी), श्री के पी परिसेल्वन, डीडीजी और एसआईओ, एनआईसी महाराष्ट्र और एनआईसी-आईवीएफआरटी मुंबई टीम जिसमें श्री संजय मैटे, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, श्री प्रसन्ना चिदंबरम, तकनीकी निदेशक, श्री कमला कन्नन गांधी, वैज्ञानिक-बी, और श्री सरवण कुमार, वैज्ञानिक-बी, शामिल थे , के मार्गदर्शन में "सीपोर्ट बैक ऑफिस मॉड्यूल" बनाया गया था।

सीपोर्ट बैक ऑफिस मॉड्यूल का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि के लिए दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है। इसे 20 फरवरी 2023 को आईसीपी बंदरगाह मुंबई में लॉन्च किया गया था और चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में सभी आईसीपी बंदरगाहों पर लागू किया जाएगा।

- वेदुला श्रीनिवास, महाराष्ट्र

एन आई सी आईवीएफआरटी टीम ने सीपोर्ट बैक ऑफिस मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आईसीपी मुंबई पोर्ट कार्यालय में मुंबई पोर्ट अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिए News पर जायें https://informatics.nic.in/news